www.sanjanabharati.com
दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित
facebook.com/Sanjanabharati

SB NEWS

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 निरंकुश अभिव्यक्ति से जुड़े सुप्रीम फैसलों...
3 ककराला में मेगा बिजली बिल समाधान शिविर का...
4 स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने किया महर्षि...

वर्ष: 9 | अंक: 264 | दिल्ली, शुक्रवार, 18 जुलाई 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क पहुंचे उपराष्ट्रपति, कही यह बड़ी बात

नई दिल्ली (एजेन्सी)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को दिल्ली में यमुना वाटिका और बांसड़ा पार्क का दौरा किया, जहां उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनका स्वागत किया। धनखड़ ने भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और राजधानी में विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रयासों की भी सराहना की और दिल्ली में उनके काम को क्रांतिकारी बताया और कहा कि रिवरफ्रंट एक प्रमुख वैश्विक आकर्षण बनेगा। पत्रकारों से बात करते हुए, धनखड़ ने कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी है। उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा किया गया कार्य क्रांतिकारी है। दिल्ली के लोग हमेशा याद रखेंगे कि उनके प्रयास फल दे रहे हैं। दिल्ली को नए फेफड़े, नई ऊर्जा प्रदान की जा रही है। क्योंकि यह एक बड़ी चुनौती थी। मुझे यकीन है कि ज्यादा से ज्यादा दिल्लीवासी इस प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण के अनुकूल सुंदरता का आनंद लेंगे, और यह अद्भुत होने वाला है। मुझे यकीन है कि रिवरफ्रंट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रिवरफ्रंट से मेल खाएगा। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बार पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद यह एक वैश्विक आकर्षण होगा।

मुंबई के चर्चगेट स्टेशन पर फूड स्टॉल में लगी आग, कोई हताहत नहीं

मुंबई (एजेन्सी)। मुंबई में पश्चिमी रेलवे (डब्ल्यूआर) के व्यस्त चर्चगेट उपनगरीय स्टेशन पर बृहस्पतिवार की सुबह एक फूड स्टॉल में आग लग गई। दो महीने से भी कम समय में इस परिसर में यह दूसरी ऐसी घटना है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पश्चिम रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारी संघ के नेताओं ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि आग सुबह करीब 8.10 बजे लगी थी, जो संभवतः स्टॉल के अंदर शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे के एक कर्मचारी की समय पर की गई कार्रवाई से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया, जिससे बड़ी त्रासदी टल गई। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि आग से प्रभावित स्टॉल में दूध, आइसक्रीम और अन्य दुग्ध उत्पाद की बिक्री होती थी, जो व्यस्त रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 के सामने स्थित है। रेलवे कर्मचारी संगठन के एक नेता ने कहा कि आग एक बड़ी त्रासदी में बदल सकती थी, लेकिन नजदीक ही मौजूद चर्चगेट क्रू लॉबी के ट्रेन मैनेजर एमएस जोशी की समय पर की गई कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने बताया कि स्टॉल से धुआं और आग की लपटे निकलती देख जोशी तुरंत हरकत में आए और सूझबूझ का परिचय देते हुए आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल किया।

अलीगढ़ के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर बस की ट्रक से टक्कर में दो मरे

अलीगढ़ (एजेन्सी)। टप्पल थाना अंतर्गत आगरा-दिल्ली यमुना एक्सप्रेवे पर बृहस्पतिवार सुबह एक निजी डबल डेकर बस की एक चलते ट्रक से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जबकि 29 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि मृतकों में बस का चालक भी शामिल है। बस कानपुर से दिल्ली जा थी। दुर्घटना में घायल चार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी वरुण सिंह ने पत्रकारों को बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि बस के चालक की आंख लगने से बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना के समय दोनों वाहन समान दिशा में जा रहे थे।

दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, मालदा में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित

उत्तर बंगाल (एजेन्सी)। पिछले 24 घंटों में उत्तर बंगाल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से व्यापक अफरा-तफरी मच गई। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में मामूली भूस्खलन, पेड़ उखड़ गए, निचले इलाकों में पानी भर गया और घरों को नुकसान पहुँचा। आईएमडी के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक उत्तर बंगाल और सिक्किम में बारिश जारी रहेगी। भारी बारिश के कारण NH10 के किनारे श्वेतिझोरा में भूस्खलन हुआ। यह इलाका सिलीगुड़ी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। भूस्खलन के कारण मलबा हटाए जाने तक यातायात प्रभावित रहा। उत्तर बंगाल के कई हिस्सों में 24 घंटे से ज्यादा समय तक तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हुई, जिससे बुधवार को भूस्खलन हुआ, घरों को नुकसान पहुँचा, पेड़ उखड़ गए और कई कस्बों में भीषण जलभराव हो गया। दार्जिलिंग ज़िले में भूस्खलन की अलग-अलग घटनाओं में छह साल की बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के सूत्रों ने बताया कि बुधवार सुबह तक 24 घंटों में दार्जिलिंग में लगभग 72 मिमी, सिलीगुड़ी में 64 मिमी और मालदा में 63 मिमी बारिश हुई। दार्जिलिंग ज़िले के पुलबाजार पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की समेत दो लोग मलबे में ज़िंदा दब गए। चचार्रे बारी जमुनी में, 32 वर्षीय उत्खनन चालक प्रणित जोगो की मलबा गिरने से मौत हो गई। लोअर गोके में 6 साल की सामंता सुब्बा की मलबे में दबकर मौत हो गई।

नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भारत24 के हरित ऊर्जा शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए। (स्रोत: पीआईबी)

सीएम रेखा गुप्ता ने गोकुलपुरी कांवड़ शिविर का उद्घाटन कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

कांवड़ यात्रा को बताया श्रद्धा, सेवा और समर्पण का संगम

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गोकुलपुरी स्थित कांवड़ शिविर का उद्घाटन किया और दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे दिल्ली में एक उत्सव जैसा माहौल है। हर कांवड़ कैंप की व्यवस्थाएं हमारी टीम, अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों द्वारा समय से पहले ही सुनिश्चित कर ली गई हैं। दिल्ली सरकार पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ अपना कर्तव्य निभा रही है। इस दौरान सांसद श्री मनोज तिवारी जी, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी एवं विधायक श्री अजय महावर जी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली के यमुना विहार में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की और भोले बाबा का आशीर्वाद लिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कांवड़ यात्रा आस्था और सेवा का प्रतीक है। हमारी सरकार प्रत्येक श्रद्धालु को पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी को असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार सभी व्यवस्थाए सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि पहले की सरकारों के दौरान कांवड़ सेवा में भारी अनियमितताएं होती थीं। मात्र 170 कैंप लगाए जाते थे, जिनमें से कई संदिग्ध संस्थाओं के नाम पर होते थे। करोड़ों रुपये टेंट माफिया की जेब में चले जाते थे और असली शिव भक्त तक सुविधाएं नहीं पहुंचती थीं। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।

सरकार द्वारा 374 शिविरों में की जा रही सभी सुविधाएं पूरी तरह सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार 374 कांवड़ कैंप लगाए गए हैं। सभी कैंपों को केवल 72 घंटे में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्रदान की गईं। इस बार कांवड़ शिविरों की अनुमतियाँ न केवल समयबद्ध रूप से जारी की गईं, बल्कि सभी व्यवस्थाएँ भी पूर्व निर्धारित समय में पूरी कर ली गईं है।

इतना ही नहीं, पहली बार सभी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है और उन्हें सीधे उनके बैंक खातों में फंड ट्रांसफर किया गया है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने शिविरों को दो किश्तों में सहायता राशि देने की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुझे खुशी है कि व्यवस्थाओं को लेकर लोगों में संतोष और उत्साह है। हमारी टीम के अथक प्रयासों से हर शिविर में साफ-सफाई, स्वास्थ्य, पेयजल, चिकित्सा सहायता, लाइट, सुरक्षा और भोजन जैसी तमाम जरूरी व्यवस्थाएँ दुरुस्त की गई हैं। मुख्यमंत्री ने सावन माह की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा देश की धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा का गौरवशाली प्रतीक है और दिल्ली सरकार इसका सम्मान करती है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर श्रद्धालु को सुलभ, सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा अनुभव मिले।मुख्यमंत्री ने शिविर में मौजूद स्वयंसेवकों और कर्मचारियों की सराहना की और दिल्लीवासियों से अपील की कि वे कांवड़ यात्रियों का स्वागत खुले दिल से करें और उन्हें हरसंभव सहयोग दें।

मुख्यमंत्री बताया कि कांवड़ समिति के चेयरमैन श्री कपिल मिश्रा सहित विभिन्न समितियों और संगठनों से यह सुझाव मिला है कि सहायता राशि को और थोड़ा बढ़ाया जाए, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता और बेहतर हो सके। दिल्ली सरकार इस सुझाव को गंभीरता से ले रही है और शिविरों की हरसंभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।

करनाल बना सुपर स्वच्छ शहर, देश में तीसरा स्थान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

करनाल हरियाणा का पहला शहर बना स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। देश के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 के परिणामों में करनाल शहर ने सुपर स्वच्छ शहर श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान हासिल कर हरियाणा को गौरवान्वित किया है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करनाल की महापौर रेनू बाला गुप्ता, नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा और हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल को सम्मानित किया।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में कुल 12500 अंक निर्धारित किए गए थे, जिसमें करनाल नगर निगम को 11067 अंक प्राप्त हुए। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण से 9057, कूड़ा मुक्त शहर से 800 और खुले में शौच मुक्त श्रेणी से पूरे 1200 अंक मिले।

सुपर स्वच्छ शहर श्रेणी में पहला स्थान मध्यप्रदेश का देवास (11692 अंक) और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का करहड़ (11088 अंक) को मिला है।

करनाल हरियाणा का पहला शहर है जिसे सुपर स्वच्छ शहर श्रेणी में देश में तीसरा रैंक मिला है। इस उपलब्धि ने प्रदेश के लिए एक नई मिसाल कायम की है। करनाल को कूड़ा मुक्त शहर की 3-स्टार रेटिंग और वॉटर प्लस स्टेटस भी मिला है।

स्वच्छता में करनाल की बड़ी उपलब्धियां: नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि करनाल को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में 98%, सोर्स सैग्रीगेशन में 77%, प्रोसेसिंग में 76%, डंपसाइट सुधार, वाणिज्यिक व आवासीय क्षेत्र, वाटर बॉडीज, शौचालयों की सफाई में 100% अंक मिले। इसके अतिरिक्त शहर में रिड्यूस, रिसाइकिल व रीयूज सेंटर स्थापित किए गए, दीवारों पर सुंदर पेंटिंग करवाई गई, और नागरिकों को लगातार जागरूक किया गया।

महापौर व निगमायुक्त ने जताया गर्व: महापौर रेनू बाला गुप्ता ने शहरवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे करनाल की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सांसद मनोहर लाल का आभार जताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और समर्थन से यह सफलता मिली है। निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने सफाई मित्रों की विशेष सराहना की और कहा कि यह उपलब्धि उनकी निष्ठा, टीमवर्क और समर्पण का फल है।

महीनों की मेहनत का नतीजा: स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम ने मार्च माह में करनाल का गहन मूल्यांकन किया था। इसमें कूड़ा प्रबंधन, साफ-सफाई, जनसहभागिता, तकनीकी व्यवस्था, जल प्रबंधन, नागरिक प्रतिक्रिया और सफाई कर्मचारियों के कल्याण जैसे बिंदुओं पर नगर निगम की कार्यशैली को आंकलित किया गया।

नगर निगम की ओर से स्वच्छता के लिए विशेष टीम गठित की गई थी, जिसने महीनों तक समर्पित प्रयास किए और शहर को हर पैरामीटर पर सशक्त बनाया।

सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने 8वीं बार 'सबसे स्वच्छ शहर' का खिताब बरकरार रखा

(एजेन्सी)।

इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कारों की घोषणा के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर को "सुपर स्वच्छ लीग शहरों" में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। इंदौर दस लाख की आबादी वाली श्रेणी में भी सबसे स्वच्छ शहर रहा, उसके बाद सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा का स्थान रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजे बृहस्पतिवार को घोषित किए गए। तीन से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा पहले स्थान पर, चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर और मैसूर तीसरे स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां आयोजित

एक कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और अन्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 10 जुलाई को, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 74वें जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्वच्छता अभियान चलाया गया। लखनऊ की महापौर सुषमा खारवाल के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने कहा, "आज लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के रक्षा मंत्री का जन्मदिन है। आज लखनऊ एक बड़े स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहा है। यह लखनऊ की जनता की ओर से उन्हें एक तोहफा है।"

50 मृत नदियों को जीवित कर योगी ने किया कमाल

(एजेन्सी)।

उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जल संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं अब जमीन पर असर दिखा रही हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम और मनरेगा के तहत किए जा रहे प्रयासों से राज्य की सूखी व विलुप्तप्राय नदियों में फिर से जीवन लौटने लगा है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक 3363 किलोमीटर लंबाई में कुल 50 नदियों का कायाकल्प किया जा चुका है, जिससे गांवों को नई ऊर्जा और किसानों को सिंचाई का बेहतर साधन मिल रहा है।

हम आपको बता दें कि योगी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर विशेष पहल करते हुए 1011 गंगा ग्राम पंचायतों में छोटी नदियों व जलधाराओं का पुनरुद्धार कराया है। इन जलस्रोतों को न केवल साफ-सुथरा किया गया, बल्कि उनकी प्राकृतिक धारा को भी पुनर्जीवित किया गया। इससे इन क्षेत्रों में जल स्तर में सुधार हुआ है और आसपास के किसानों को बड़ी राहत मिली है। मनरेगा के तहत 86 अन्य कार्यों को चिह्नित कर नदियों की साफ-सफाई, गहरीकरण, तटबंध निर्माण, पौधरोपण, जलधारा पुनर्स्थापन और जलग्रहण क्षेत्र विकास जैसे कार्य किए गए जिनका व्यापक असर देखने को मिला है।

देखा जाये तो नदियों के पुनरुद्धार से सिर्फ पर्यावरण ही नहीं सुधरा बल्कि कई स्थानों पर इन जलधाराओं से जुड़े सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का महत्व भी बढ़ा है। लोग अब इन जलस्रोतों को

लेकर जागरूक हुए हैं और स्थानीय स्तर पर भी संरक्षण के प्रयासों में सहभागिता निभा रहे हैं। योगी सरकार की यह पहल उत्तर प्रदेश को जल संकट से उबारने, ग्रामीणों को रोजगार देने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की एक सशक्त व कारगर रणनीति बनकर उभरी है।

हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन को अपनी प्राथमिकता में रखा है। जिन छोटी-छोटी नदियों को लोग लगभग भूला चुके थे, जिन्हें नाले या गंदगी के अड्डे के रूप में देखा जाने लगा था, आज उन्हीं नदियों में फिर से स्वच्छ जलधारा बहने लगी है। यह केवल पर्यावरणीय सफलता नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रमाण है। इसका सबसे ताजा और सकारात्मक उदाहरण फिरोजाबाद जिले में देखने को मिल रहा है, जहां वर्षों बाद नदियों का पुनर्जीवन स्थानीय जनता के लिए आशा और उत्साह का कारण बन रहा है।

फिरोजाबाद के सिरसागंज, शिकोहाबाद और टूंडला क्षेत्र में बहने वाली 108 किलोमीटर लंबी सिरसा जैसी छोटी नदियां गंदगी, अतिक्रमण और जलस्रोतों के सूख जाने के कारण लगभग मृतप्राय हो चुकी थीं। नदियों में गंदा पानी, प्लास्टिक, सीवर ने प्राकृतिक जलधारा को खत्म कर दिया था। इससे क्षेत्र में भूजल का स्तर गिर गया, खेती के लिए पानी की भारी समस्या बनी। इसको देखते हुए योगी सरकार ने 'नमामि गंगे मिशन' और 'संचारी जलशक्ति अभियान' के तहत इन नदियों को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। नदियों से अतिक्रमण हटाया गया। क्लीनिंग, डी-सिल्टिंग (गाद हटाना), गंदे नालों का पानी रोककर ट्रीटमेंट के बाद छोड़ा गया। अब बारिश के पानी को संग्रह कर नदी में छोड़ा जा रहा है ताकि जलधारा स्थायी बनी रहे।

फिरोजाबाद के लोग दशकों से जिस नदी को मृत मान चुके थे, अब उसे बहते देखना किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। देखा जाये तो योगी सरकार का यह अभियान सिर्फ नदियों को ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करने का मॉडल बन रहा है। फिरोजाबाद से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक, हर नदी के पुनर्जीवन से गांव-गांव में भरोसा लौटा है कि सरकार यदि चाहे तो मरी हुई नदी में भी फिर से जीवन बह सकता है।

सीएम रेखा गुप्ता ने नंद नगरी डिपो में पूर्णतः स्वचालित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की रखी आधारशिला

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीटीसी नंद नगरी डिपो में अत्याधुनिक और पूर्णतः स्वचालित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की आधारशिला रखी। यह केंद्र दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में तकनीकी पारदर्शिता और सुरक्षा के एक नए युग की शुरूआत करेगा। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ पंकज सिंह, सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली विधान सभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायक डॉ जितेंद्र महाजन, अजय महावर सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली की सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए आधुनिक परिवहन प्रणाली विकसित कर रही है। नंद नगरी डिपो में यह नया ATS ट्रांस-यमुना क्षेत्र के लाखों वाहन चालकों को राहत देगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में बढ़ते वाहनों की संख्या को देखते हुए, सटीक, निष्पक्ष और डिजिटल तकनीकों से युक्त फिटनेस परीक्षण प्रणाली समय की मांग है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिल्ली में 1.53 करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहन हैं, जिनमें से लगभग 6.5 लाख वाणिज्यिक वाहनों को हर साल

फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। फिर भी, फिलहाल केवल एक ही ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (झुलझुली में) कार्यरत है, जहां सालाना केवल 47,919 वाहनों का परीक्षण हो पाता है।

मुख्यमंत्री ने एटीएस की विशेषताओं को साझा करते हुए कहा कि यह नया ऑटोमैटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) पूरी तरह डिजिटल होगा और इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी। यह अत्याधुनिक केंद्र 40 मीटर ×26 मीटर के प्री-इंजीनियर्ड भवन में संचालित होगा, जिसमें आठ कार्यात्मक कक्ष, टॉयलेट ब्लॉक, पैंट्री और पैनल रूम जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने आगे बताया कि यह एटीएस चार-लेन प्रणाली पर आधारित होगा, जिसमें दो लेन भारी वाहनों, एक लेन हल्के वाहनों और एक लेन दोपहिया वाहनों के परीक्षण के लिए समर्पित होगी। यहां वाहनों के उत्सर्जन, रोलर ब्रेक, सस्पेंशन (सामने और पीछे), अंडरबॉडी निरीक्षण और हेडलाइट एलाइनमेंट जैसे उन्नत परीक्षण किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस केंद्र की वार्षिक परीक्षण क्षमता 72,000 वाहनों की होगी, जिसमें 20,000 दोपहिया वाहन भी शामिल हैं। इसके संचालन से दिल्ली परिवहन निगम को प्रतिवर्ष लगभग रु3 करोड़ की आय होने की संभावना है।

इस परियोजना की अनुमानित लागत रु10 करोड़ है और इसके लिए आवश्यक निधि परिवहन विभाग की राज्य पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है। उन्होंने आगे बताया कि तकनीकी सलाहकार के रूप में भारत सरकार की संस्था इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को नियुक्त किया गया है ताकि पूरा प्रोजेक्ट भारत सरकार के मानकों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अनुरूप हो।

सम्पादकीय

स्वच्छता एवं नशामुक्ति

इस धरा पर जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव के लिए प्रकृति ने पर्याप्त खाद्य पदार्थ दिए हैं परंतु अति लालच के चलते मानव ने प्रकृति का शोषण करना शुरू कर दिया है। इसमें कोई अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि मानव ने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए पर्यावरण का अत्यधिक नुकसान किया है और इसका परिणाम आज उसे ही भुगतना भी पड़ रहा है। कई देशों में तो भयंकर गर्मी में वहां के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं जिनसे जान और माल की भारी हानि हो रही है। हम पर्यावरण के सम्बंध में बढ़ चढ़ कर चर्चाएं तो करते हैं परंतु आज हमारे गावों में खेत, प्लाटों में परिवर्तित हो गए हैं। हमारे खेतों पर शोपिंग काम्प्लेक्स एवं मॉल खड़े हो गए हैं जिससे हरियाली लगातार कम होती जा रही है। बीते कुछ वर्षों में कंकरीट की इमारतों में अत्यधिक वृद्धि एवं भूमि प्रयोग में बदलाव के चलते भारत में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। देश के महानगर अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं। अर्बन हीट आइलैंड वह क्षेत्र होता है जहां अगल-बगल के इलाकों से अधिक तापमान रहता है। कई स्थानों पर अत्यधिक गर्मी के पीछे अपर्याप्त हरियाली, अधिक आबादी, घने बसे घर और इंसानी गतिविधियां जैसे गाडियों और गैजेट से निकलने वाली हीट आदि कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। कार्बन डाईआक्साइड और मेथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों एवं कूड़ा जलाने से भी गर्मी बढ़ती है। राजधानी दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है। जहां चारों दिशाओं में बने डंपिंग यार्डों में आग लगी ही रहती है और लोगों का सांस लेना भी अब दूभर हो रहा है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन रहित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया हुआ है। यद्यपि पर्यावरण रक्षा में भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं लेकिन यह प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक देशवासी प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक अत्यधिक शोषण करना बंद नहीं करते। शहरों के बढ़ते तापमान की रोकथाम हेतु जरूरी है कि मौसम और वायु प्रवाह का ठीक तरह से नियोजन किया जाए। हरियाली का विस्तार, जल स्रोतों की सुरक्षा, वर्षा जल संचय, वाहनों एवं एयर कंडीशंस की संख्या की कमी से ही हम प्रचंड गर्मी को कम कर सकते हैं। पृथ्वी का तापमान घटेगा तभी मानव सुरक्षित रह पाएगा। उक्त संदर्भ में यह हम सभी भारतीयों के लिए हर्ष का विषय होना चाहिए कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन मौजूद हैं जो सदैव ही सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सेवा कार्य करने वाले संगठनों को साथ लेकर, देश पर आने वाली किसी भी विपत्ति में आगे आकर, सेवा कार्य करना प्रारम्भ कर देते हैं। भारत के पर्यावरण में सुधार लाने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो बाकायदा एक नई पर्यावरण गतिविधि को ही प्रारम्भ कर दिया है। जिसके अंतर्गत समाज में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले संगठनों को साथ लेकर संघ द्वारा देश में प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करने का अभियान प्रारम्भ किया गया है और देश में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की मुहिम प्रारम्भ की गई है। साथ ही, विभिन्न शहरों को स्वच्छ एवं नशामुक्त बनाने हेतु भी विशेष अभियान प्रारम्भ किए हैं। उदाहरण के तौर पर ग्वालियर को स्वच्छ, नशामुक्त एवं प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का बीड़ा उठाया गया है। इसी संदर्भ में ग्वालियर महानगर में विविध संगठनों के दायित्ववान कार्यकर्ताओं का दो दिवसीय शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर के एक विशेष सत्र में इस बात पर विचार किया गया कि ग्वालियर महानगर को स्वच्छ एवं नशामुक्त बनाया जाना चाहिए। उक्त शिविर के समापन के पश्चात उक्त समस्याओं के हल हेतु विविध संगठनों के दायित्ववान कार्यकर्ताओं की तीन बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में विस्तार से विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि कुछ चिन्हित कार्यकर्ताओं को विभिन्न मठ, मंदिरों, स्कूलों, संस्थानों आदि में विषय प्रस्तुत करने हेतु भेजा जाए ताकि उक्त समस्याओं के हल में समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस संदर्भ में चुने गए 60 कार्यकर्ताओं के लिए एक वक्ता कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इन चिन्हित कार्यकर्ताओं को विभिन संस्थानों में विषय प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था ताकि उक्त समस्याओं के हल करने हेतु समाज को भी साथ में लेकर कार्य को सम्पन्न किया जा सके। साथ ही, ग्वालियर को प्रदूषण मुक्त सुंदर नगर बनाए जाने के अभियान को स्थानीय जनता के बीच ले जाने हेतु, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर दिनांक 25 दिसम्बर 2024 को, ग्वालियर के चुने हुए 29 चौराहों पर मानव श्रृंखलाएं बनाई गई थी, लगभग 8,000 नागरिकों ने इस मानव श्रृंखला में भागीदारी की थी। इसी प्रकार, ग्वालियर को व्यसन मुक्त नगर बनाए जाने के अभियान को स्थानीय जनता के बीच ले जाने हेतु, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस एवं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर, दिनांक 12 जनवरी 2025 को एक विशाल मेराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजन में स्थानीय प्रशासन का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ एवं लगभग 6,000 नागरिकों ने इस मेराथन दौड़ में भाग लिया था। संघ के ग्वालियर विभाग द्वारा ग्वालियर महानगर में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने की मुहिम प्रारम्भ की गई। जिसके अंतर्गत ग्वालियर के कई विद्यालयों में वहां के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को साथ लेकर स्वयंसेवकों द्वारा नगर में भारी मात्रा में पौधारोपण किया गया।

जयंती

कादम्बिनी गांगुली

जन्म-18 जुलाई, 1861, भागलपुर, बिहार; मृत्यु-3 अक्टूबर, 1923, कलकत्ता) भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजीशियन थीं। यही नहीं कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव भी कादम्बिनी गांगुली को ही प्राप्त है। कादम्बिनी गांगुली पहली दक्षिण एशियाई महिला थीं, जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाओं की लचर स्थिति पर भी काफी कार्य किया। बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं से कादम्बिनी बहुत प्रभावित थीं। उनमें देशभक्ति की भावना बंकिमचन्द्र की रचनाओं से ही जागृत हुई थी।

पुण्यतिथि

अब्दुल हमीद कैसर

जन्म-5 मई, 1929, झालावाड़, राजस्थान; मृत्यु-18 जुलाई, 1998) भारत के जाने-माने देशभक्तों में से थे। कैसर विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। गरीबों के लिए इनके दिल में बहुत प्यार था। इनके मन में बचपन से ही देशभक्ति की भावना जाग उठी थी, क्योंकि जिस विद्यालय में ये शिक्षा ग्रहण करते थे, वहाँ छात्रों में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने की भावना भरी जाती थी।

कल मिलेंगे

एक बार 5 डॉक्टरों ने मिलकर एक घोड़े का ऑपरेशन किया,
ऑपरेशन करने के बाद बड़े डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा-देखो कोई औजार तो नहीं छूट गया पेट में,
कंपाउंडर बोला-औजार तो सब हैं, लेकिन डॉक्टर गुप्ता नहीं दिखाई दे रहे!

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।
RNI No. : DELHIN/2016/70240
Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

निरंकुश अभिव्यक्ति से जुड़े सुप्रीम फैसलों का स्वागत हो

आज के दौर में हमें विचार संयम और वाणी संयम को अपनी संस्कृति और लोकतंत्र की आधारशिला बनाना होगा। जैसाकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि बोलने से पहले तीन बार सोचो, क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह दूसरों को आहत तो नहीं करेगा? संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन उसके साथ आत्मानुशासन और समाजहित की अपेक्षा भी करता है

-ललित गर्ग

सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंटी सोशल अभिव्यक्ति की सुनवाई करते हुए समय-समय पर जो कहा, वह जहां संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से खासा अहम है वहीं एक संतुलित एवं आदर्श राष्ट्र एवं समाज व्यवस्था का आधार भी है। सोशल मीडिया मंचों पर एंटी सोशल अभिव्यक्ति के चलते उपजी विभाजनकारी एवं विध्वंसकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश की जरूरत बताते हुए देश की शीर्ष अदालत ने आत्म-नियमन, वाणी संयम एवं विचार संयम की जरूरत बतायी है। धर्म विशेष के देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के चलते कई राज्यों में प्राथमिकी दर्ज हुई एवं यह याचिका दायर की गई। दरअसल, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा दायर इसी याचिका पर विचार करते हुए कहा कि समाज में विद्वेष, घृणा व नफरत फैलाने वाले संदेश समरसता, सौहार्द एवं सद्भावना के भारतीय परिवेश के लिये गंभीर चुनौती बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ी इन जटिल होती स्थितियों को गंभीरता से लिया और अनेक धुंधलकों को साफ किया है। अदालत का कहना था कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का मूल्य समझना चाहिए। साथ ही इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आत्म-संयम बरतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े अनेक मामलों के साथ-साथ ताजा मामले में जो फैसले किए हैं और इस दौरान जो टिप्पणियां की हैं, उसके निहितार्थों को समझते हुए इन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जुड़े फैसलों रूपी उजालों का स्वागत होना ही चाहिए।

आज सोशल मीडिया जैसे मंचों के बेजा इस्तेमाल की प्रवृति बढ़ रही है, फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब जैसे सोशल मंचों एवं टीवी चैनलों पर ऐसी सामग्री परोसी एवं प्रस्तुत की जा रही है, जो अशिष्ट, अभद्र, हिंसक, भ्रामक, राष्ट्र-विरोधी एवं समुदाय विशेष के लोगों को आहत करने वाली होती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को जोड़ना नहीं, तोड़ना है। इन सोशल मंचों पर ऐसे लोग सक्रिय हैं, जो तोड़-फोड़ की नीति में विश्वास करते हैं, वे चरित्र-हनन और गाली-गलौच जैसी औछी हरकतें करने के लिये उद्यत रहते हैं तथा उच्छृंखल एवं विध्वंसात्मक नीति अपनाते हुए अराजक माहौल बनाते हैं। एक प्रगतिशील, सभ्य एवं शालीन समाज में इस तरह की हिंसा, अश्लीलता, नफरत और भ्रामक सूचनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन विडम्बना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के चलते सरकार इन अराजक स्थितियों पर काबू नहीं कर पा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने चेताया है कि यदि सोशल मीडिया पर विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगता तो सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है, जो एक अच्छी स्थिति नहीं होगी। आज सोशल मीडिया, समाचार चैनलों और राजनीतिक मंचों पर जिस प्रकार की उग्र भाषा, झूठे आरोप, धार्मिक विद्वेष और भावनात्मक उकसावे देखे जा रहे हैं, वे न केवल समाज को विभाजित कर रहे हैं, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद की गरिमा को भी ठेस पहुँचा रहे हैं। यही वजह है कि कोर्ट को कहना पड़ा कि वह नियमन के लिये दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है। दरअसल, अदालत का मानना था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, इसके तहत प्रत्येक नागरिक को विचार, वाणी, लेखन, चित्रण आदि के माध्यम से स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन आज इस अधिकार के दुरुपयोग की घटनाएं जिस प्रकार सामने आ रही हैं, वह चिंता का विषय बन चुकी हैं। इसलिए आज जरूरत है विचार संयम और वाणी संयम की। इसीलिये अनुच्छेद 19(2) इसके कुछ उचित प्रतिबंध भी निर्धारित करता है जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, राज्य की अखंडता, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अश्लील या अनैतिक भाषण, अदालत की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसावा एवं अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों से जुड़ी अराजकता पर प्रतिबंध, इन प्रतिबंधों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वतंत्रता का उपयोग अनुशासन और राष्ट्रीय हितों की मर्यादा में हो। संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत मिली आजादी असीमित कदापि नहीं है।

ताजा मामलों में कई राज्यों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के नियमन को लेकर सरकारी कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कई जगह विचारों की अभिव्यक्ति व कार्टून आदि बनाने को राजनीतिक दुराग्रह बताते हुए लोगों को गिरफ्तार तक किया गया है। जिसे राजनीतिक दलों द्वारा बदले की भावना से की कार्रवाई बताया जाता रहा है। आरोप लगाया जाता रहा है कि सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के अनुरूप अमर्यादित एवं अशालीन अभिव्यक्ति के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन दूसरे राज्य में अन्य राजनीतिक दल की सरकार में यही अभिव्यक्ति अपराध बन जाती है। कोई नहीं चाहता कि आम नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी को सरकार नियंत्रित करे। सही मायनों में लोगों को समझना चाहिए कि देश की एकता व अखंडता बनाये रखना मौलिक कर्तव्य ही है। अदालत ने इस बाबत सवाल भी किया कि नागरिक स्वयं को संयमित क्यों नहीं कर सकते? राजनीतिक दल, धार्मिक नेता या उग्रवादी कार्यकर्ता क्यों समाज में विषवमन करते हुए विवादास्पद एवं वर्ग-धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले कटू एवं कड़वे बयान देते हैं? कोर्ट का मानना था कि लोग तभी अभिव्यक्ति की आजादी का आनन्द ले सकते हैं जब यह संयमित ढंग से व्यक्त की जाए। शीर्ष अदालत की पीठ का मानना था कि नागरिकों के बीच भाईचारा होना चाहिए, तभी समाज में नफरत से मुकाबला किया जा सकता है। तभी हम गंगा-जमुनी सांझा संस्कृति के राष्ट्र एवं समाज का निर्माण कर सकते हैं।

आज के दौर में हमें विचार संयम और वाणी संयम को अपनी संस्कृति और लोकतंत्र की आधारशिला बनाना होगा। जैसाकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि बोलने से पहले तीन बार सोचो, क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह दूसरों को आहत तो नहीं करेगा? संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन उसके साथ आत्मानुशासन और समाजहित की अपेक्षा भी करता है। यदि हम इसे समझ लें, तो हमारा लोकतंत्र और अधिक सशक्त और समरस बन सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन जब यह सीमा पार करती है तो देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को खतरा उत्पन्न होता है। सुप्रीम कोर्ट बार-बार यह संदेश दे रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी और मर्यादा जुड़ी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का भी मानना था कि यदि आपके शब्द राष्ट्र को प्रेरित करने की बजाय भटकाने लगे, तो वह आजादी नहीं, अराजकता है। सोशल मीडिया आज एक ऐसा ही अस्त्र बन गया है जो जरा सी चूक से घातक साबित हो सकता है। वास्तव में हर नागरिक को इतना सचेत व जागरूक होना जरूरी है कि वह विभिन्न स्रोतों से आने वाली सामग्री से जुड़ी मंशा को समझ सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मर्यादा टूटे तो वह विरोध नहीं, विघटनकारी गतिविधि बन जाती है। ऐसी ही विघटनकारी गतिविधियां सोशल मीडिया पर विनाशकारी स्वरूप लेती जा रही है। यह निर्विवाद सत्य है कि विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों द्वारा सोशल मीडिया मंच का जमकर दुरुपयोग किया जाता रहा है। वहीं लोगों का कसूर यह है कि दल विशेष के एजेंडे वाली सामग्री को वे बिना पढ़े, दूसरे लोगों व समूहों में शेयर कर देते हैं। दरअसल, आम नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि सोशल मीडिया पर उनका संयमित व्यवहार कैसा होना चाहिए? बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है कि सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही सामग्री की कितनी संवेदनशीलता है? कई लोग जाने-अनजाने में ऐसी सामग्री दूसरे व्यक्तियों व समूहों में शेयर कर देते हैं जो राष्ट्र एवं समाज विरोधी हो सकती है। दरअसल, वे उसकी मूल सामग्री को बनाने वाले के छिपे एजेंडे को नहीं भांप पाते। कभी-कभी भावावेश में लोग ऐसे कदम उठा देते हैं। जाहिर है, उच्छृंखल हुए बिना आजादी के उपयोग में ही नागरिक का भी भला है और समाज का भी।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

भारत की प्रगति पर ब्रेक के बाद उठती अमेरिकी खींझ के वैश्विक कूटनीतिक मायने को ऐसे समझिए

देखा जाए तो ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के लिए रूस को और 50 दिनों की मोहलत दी है, और यही डेडलाइन उन्होंने उन देशों के लिए रखी है, जो रूस से तेल समेत दूसरे सामान खरीदते हैं। यानी भारत और चीन, जिनके मतलबी सम्बन्ध रूस और अमेरिका दोनों से हैं। यही वजह है कि अमेरिका की नई धमकी है कि इसके बाद इन देशों पर शत (100) प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा

-कमलेश पांडेय

आपने 'रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं टूटी' वाली कहावत सुनी होगी। यही हालात आज दुनिया के थानेदार अमेरिका की है। एक ओर रूस के दृढ़ निश्चय से यूक्रेन में नाटो देश यानी अमेरिका-यूरोप की खुराफात बुरी तरह से पिट चुकी है। वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान पर भारत के दमदार पलटवार और इजरायल पर ईरान के अप्रत्याशित पलटवार से अमेरिकी वैश्विक बादशाहत को करारा तमाचा लगा है। इन घटनाओं से साफ है कि अमेरिकी और यूरोपीय पश्चिमी देश अब अपराजेय नहीं रहे, बल्कि उनकी फूट डालो और शासन करो की नीति को एशियाई और अफ्रीकी देश भांप चुके हैं।

इधर पूर्वी देशों में चीनी जिद्द से रूस (सोवियत संघ के जनक) और भारत की अमेरिका विरोधी नीति सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि भारत विरोधी पाकिस्तान से अमेरिका के अलावा अब चीन भी प्रेम करने लगा है। इससे उत्तर कोरिया भी भारत के साथ खुलकर मैदान में नहीं आ पा रहा है, जबकि वह चीन और रूस का मित्र है। दो टूक शब्दों में कहा जाए तो रूस अब अमेरिकी और यूरोपीय देशों को करारा जवाब दे सकता है, भारत से दिलवा सकता है, लेकिन चीन के पाकिस्तान प्रेम और भारत से रणनीतिक शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा से एशियाई देशों में अभी भी अमेरिकी-यूरोपीय दाल गल रही है।

ऐसा इसलिए कि वैश्विक कूटनीति में सभी देश अपना-अपना हित देख रहे हैं। इधर भारत के विश्वव्यापी कूटनीतिक प्रभावों से अमेरिका-यूरोप व अमेरिका-अरब देशों में जो रणनीतिक व कारोबारी खटास की नींव पड़ी है, अरब देशों में अमेरिकी चौधराहट को जो तगड़ा धक्का लगा है, उससे अमेरिका बौखलाया हुआ है। कहाँ वह भारत को अपने पाले में करके पहले चीन को सबक सिखाता और फिर पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को कमजोर करता। लेकिन भारत के चतुर मोदी प्रशासन ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए जो वफादारी दिखाई, उससे अमेरिकी शतरंज की चाल बिखर गई और उसके हथियार निमार्ता कम्पनियों के तमाम अरमानों पर पानी फिर गया।

ऐसा इसलिए कि भारत के प्रशासन ने सूझबूझ के साथ कदम बढ़ाते हुए अमेरिकी, रूसी, चीनी, यूरोपीय, अरब, अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण अमेरिकी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ जो व्यवहारिक और गिव एंड टेक भरे कदम उठाए, उससे जहां एक ओर रूस-भारत के सम्बन्धों को मजबूती मिली, वहीं अमेरिका और उसके कारोबारी पार्टनर चीन (अब प्रतिस्पर्धी देश) की आर्थिक गतिविधियों और सैन्य रणनीतियों को करारा जवाब मिला। इसी के बदौलत जहां अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते पटरी पर लौटे, वहीं इजरायल से मित्रता के बावजूद ईरान से सम्बन्ध खराब नहीं हुए। इन्हीं सब बातों को लेकर अमेरिका बौखलाया हुआ है।

दरअसल, अमेरिका को गलतफहमी है कि अमेरिका-यूरोप का सहयोग लेकर भारत भी चीन की तरह आशातीत प्रगति कर चुका है और जब तक ये दोनों देश रूस के साथ मित्रता रखेंगे, तब तक नाटो देशों की वैश्विक बादशाहत को रूस, भारत, ईरान जैसे देशों से चुनौती मिलती रहेगी। यही वजह है कि रूस के साथ व्यापार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया चेतावनी भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चल रही बातचीत में अड़चन पैदा कर सकती है। ऐसा इसलिए कि यूक्रेन युद्ध रुकवाने में नाकाम रहे डोनाल्ड ट्रंप अब दूसरे जरियों से मॉस्को पर दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि इसमें सफलता की गारंटी लेशमात्र भी नहीं है और इससे दुनिया में नया तनाव पैदा हो सकता है।

देखा जाए तो ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के लिए रूस को और 50 दिनों की मोहलत दी है, और यही डेडलाइन उन्होंने उन देशों के लिए रखी है, जो रूस से तेल समेत दूसरे सामान खरीदते हैं। यानी भारत और चीन, जिनके मतलबी सम्बन्ध रूस और अमेरिका दोनों से हैं। यही वजह है कि अमेरिका की नई धमकी है कि इसके बाद इन देशों पर शत (100) प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। उधर, यही बात नैटो महासचिव मार्क रूट भी दोहरा रहे हैं। उन्होंने तो सीधे-सीधे भारत, चीन और ब्राजील का नाम लिया कि इन देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शांति के लिए बात करनी चाहिए। क्योंकि ये देश ही रूस से तेल खरीदते हैं।

बताया जाता है कि कुछ वक्त पहले तक ट्रंप इस बात पर डटे थे कि किसी भी सूरत में यूक्रेन युद्ध रुकना चाहिए। लेकिन, जब उनका दबाव रूस पर कारगर नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी चुगलखोर रणनीति बदल दी। अब वह यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के लिए तैयार हैं और पूछ भी रहे हैं कि क्या रूस पर हमला कर लोगे? ऐसा इसलिए कि अमेरिकी और दूसरे पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस को झुकाने में बाकी दुनिया भी उसका साथ दे-खासकर भारत और चीन। उल्लेखनीय है कि साल 2022 में, जब से रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिका की यही कोशिश है। पहले भी उसने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर सवाल उठाए थे और यहां से उसे इसका माकूल जवाब भी मिला था कि दुनिया के हर हिस्से के अपने-अपने हित होते हैं और इस पर यदि अपनी अपनी न चलाई जाए, तो यही सबके हित में बेहतर है। अमेरिका-यूरोप जो काम खुद करते हैं, वही करने के लिए पूरब के देशों को रोकते हैं, ताकि उनकी वैश्विक बादशाहत को रूसी-चीनी-भारतीय चुनौती कभी नहीं मिले। इसके लिये पाकिस्तान, अरब देश और ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान आदि उनके मोहरे हैं।

जहां तक तेल का व्यापार का सवाल है तो साल 2024-25 में भारत और रूस के बीच 68.7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा फोकस में रहा तेल। जबकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले तक देश की ज्यादातर तेल जरूरत मिडल ईस्ट से पूरी होती थी और तब रूस से केवल एक फीसदी क्रूड ऑयल ही आता था। लेकिन आज यह हिस्सा एक तिहाई से ज्यादा है। मई 2025 में भारत ने रूस से हर दिन करीब 20 लाख बैरल तेल मंगाया था। इस व्यापार के पीछे साधारण-सा लॉजिक है, बचत। इसलिए भारत अमेरिका के समक्ष अपनी बात मजबूती से रखता है।

कहना न होगा कि हर द्विपक्षीय वैश्विक रिश्ते को मुनाफे में तौलने वाले कारोबारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत-रूस संबंधों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वाकई उनके दबाव बनाने के पीछे एक वजह ब्रिक्स (इफ्क्ष्र) नामक वैश्विक संगठन भी है, जिसकी सक्रियता उन्हें पसंद नहीं आ रही। क्योंकि इससे जी-7 देशों को चुनौती मिलती है। इसलिए भारत को इस मामले में अमेरिका के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए, जिसे पिछली बाइडन सरकार ने समझा भी था। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप रूस को जी-7 में शामिल करके जी-8 और चीन को शामिल करके जी-9 बनाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया की तीसरी बड़ी सैन्य शक्ति और चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति भारत को पीछे धकेलना चाहते हैं, जिससे भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अमेरिकी वैश्विक चौधराहट धीरे धीरे चीन द्वारा खत्म कर दी जाएगी। शुरूआत हो चुकी है।

इसलिए भारत की आशातीत प्रगति पर ब्रेक के बाद उठती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खींझ के वैश्विक कूटनीतिक मायने स्पष्ट हैं। भारत को अपने गुटनिरपेक्ष पथ पर अडिग रहना चाहिए। वह ग्लोबल साउथ को साधकर एक साथ अमेरिकी-चीनी चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम है। कभी बात-बात में युद्ध छेड़-छिड़वा देने वाला अमेरिका इसलिए चन्द्रायण व्रत कर लिया है, क्योंकि पहले वियतनाम में, फिर लीबिया, में, ततपश्चात अफगानिस्तान में जिस तरह से वह अपने मिशन में फेल हुआ, उससे इराकी सफलता और सीरियाई विफलता ने और अधिक दुःखदाई बना दिया। इसलिए अब अमेरिका खुद युद्ध नहीं करेगा, बल्कि यूक्रेन, इजरायल, पाकिस्तान आदि की पीठ पर हाथ रखकर करवाएगा। भारत इसे समझता है। इसलिए वह अमेरिकी जाल में नहीं फंसा, बल्कि चिड़ियों की तरह अमेरिकी जाल ही ले उड़ा, जिसे रूसी चूहे कुतर रहे हैं! शिकारी अमेरिका मन मसोसकर पाकिस्तान की शरण में शरणागत बना बैठा है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

शेख हसीना ने बांग्लादेश में पलटा खेल! गोपालगंज नरसंहार से बढ़ा बवाल

(एजेन्सी)।

गोपालगंज में हुई घातक हिंसा के बाद एक तीखे बयान में पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी डॉ. मुहम्मद यूनुस और उनके समर्थकों पर बांग्लादेश की मूल पहचान को नष्ट करने और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के समाधि स्थल को अपवित्र करने के लिए एक "बर्बर साजिश" रचने का आरोप लगाया है। यह बयान गोपालगंज के तुंगीपाड़ा में हुई जानलेवा झड़पों के एक दिन बाद आया है। यह झड़प नवगठित राष्ट्रीय आम सहमति पार्टी (एनसीपी) के समर्थकों के नेतृत्व में एक विवादास्पद गोपालगंज मार्च के दौरान हुई थी। माना जा रहा है कि इस पार्टी को यूनुस का समर्थन प्राप्त है।

बंगबंधु समाधि परिसर पर गैरकानूनी और भड़काऊ भीड़ के हमले को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम एक दर्जन नागरिकों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की आशंका है।

इस साल की शुरूआत में पद से हटाए जाने के बाद अपने पहले बड़े राजनीतिक हस्तक्षेप में, शेख हसीना ने यूनुस पर निशाना साधते हुए उन्हें हत्यारा-फासीवादी, राष्ट्र-विरोधी षड्यंत्रकारी और भीड़ आतंकवाद का गॉडफादर कहा। उन्होंने कहा कि देश ने देखा कि किसने हमारे झंडे, हमारे संविधान और राष्ट्रपिता की समाधि का अपमान किया। बंगबंधु और बांग्लादेश एक हैं। बंगबंधु पर कोई भी हमला इस देश की आत्मा पर हमला है और बंगाली लोग इसे माफ नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि यह हिंसा 5 अगस्त की घटना का ही एक रूप है। अवामी लीग के कार्यालयों और स्मारकों पर पहले हुए हमलों का ज़िक्र करते हुए और यूनुस पर उग्रवादी तत्वों को भड़काने और राज्य को अस्थिर करने का आरोप लगाया।

साइबर आतंकवाद से लड़ने के लिए के के मेनन की वापसी

(एजेन्सी)।

के के मेनन अभिनीत 'स्पेशल ऑप्स' का आगामी सीजन, अपनी प्रारंभिक रिलीज तिथि से एक सप्ताह की देरी के बाद, 18 जुलाई को प्रीमियर के लिए तैयार है। यह बहुप्रतीक्षित सीरीज एक जबरदस्त जासूसी थ्रिलर के रूप में अपनी परंपरा को जारी रखेगी, और अब इसका ध्यान साइबर युद्ध पर केंद्रित है। साइबर आतंकवाद के खतरों की पड़ताल करते हुए, यह श्रृंखला डिजिटल सुरक्षा खतरों के यथार्थवादी चित्रण के साथ दर्शकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखती है। पारंपरिक जासूसी से साइबर युद्ध की ओर विषयगत बदलाव वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों की बदलती प्रकृति को रेखांकित करता है और दर्शकों को इन मुद्दों पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। दर्शक तीव्र एक्शन, रणनीतिक योजना और नाटकीय कहानी के मिश्रण की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि 'स्पेशल ऑप्स 2' इन समकालीन मुद्दों से निपटता है।

शो के प्रशंसक के के मेनन के किरदार हिम्मत सिंह की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो डिजिटल आतंकवाद के नए खतरे के खिलाफ प्रयासों का नेतृत्व करेगा। वर्तमान वैश्विक चिंताओं से जुड़ी एक कहानी के साथ, यह सीरीज साइबर खतरों की जटिलताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का पता लगाने का वादा करती है। आगामी सीजन साइबर युद्ध पर केंद्रित होगा। मेनन हिम्मत सिंह की अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे, जो डिजिटल आतंकवाद के इस नए खतरे के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करते हैं। शो साइबर खतरों की पेचीदगियों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके प्रभावों पर गहराई से प्रकाश डालने का वादा करता है। "इस बार, हर कोई निशाने पर है" की टैगलाइन आज की दुनिया में साइबर आतंकवाद के बड़े खतरे को दर्शाती है।

ताहिर राज भसीन नए खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए हैं। 16 जून को रिलीज हुए ट्रेलर ने अपने अप्रत्याशित कथानक और मनोरंजक कहानी से दर्शकों के बीच पहले ही उत्सुकता जगा दी है। शो की शूटिंग बुडापेस्ट, तुर्की और जॉर्जिया सहित कई अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर हुई है, जो इसके सिनेमाई आकर्षण को और बढ़ा देता है। अन्य कलाकारों में करण टैकर, प्रकाश राज, विनय पाठक और दिलीप ताहिल शामिल हैं।

पहले, स्पेशल ऑप्स 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे 18 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया। रिलीज से कुछ दिन पहले, निमार्ताओं ने प्रीमियर में देरी की घोषणा की। के के मेनन ने खुद इंस्टाग्राम पर नई रिलीज डेट की घोषणा की। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, "स्पेशल ऑप्स के सभी प्रशंसकों के लिए, दूसरा सीजन अब 11 जुलाई की बजाय 18 जुलाई को स्ट्रीम होगा।

चौथे टेस्ट से कटेगा करुण नायर का पत्ता!

(एजेन्सी)। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट 23 जुलाई से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरूआती तीन मैचों में भारत के ज्यादातर बल्लेबाजों ने बड़े रन बटोरे हैं लेकिन करुण नायर को दूसरा मौका दिया फिर भी वह उसे भूना नहीं पाए। चौथे टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन तय होने पर सिर्फ उन्हीं का नाम हट सकता है। आठ साल बाद टीम इंडिया के लिए वापसी कर रहे करुण नायर ने अपनी 6 पारियों में से ज्यादातर में अच्छी शुरूआत की लेकिन वह उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। वहीं पूर्व भारतीय विकेटकीपर दीप दासगुप्ता का कहना है कि सुदर्शन को वापस लाने का समय आ गया है। लॉर्ड्स में दूसरी पारी में वह ब्रायडन कार्स की अंदर आती गेंद की लाइन एंव लेंथ का सही अनुमान नहीं लगा पाए और आउट हो गए। तीसरे नंबर पर भारत को नायर से मजबूती दिलाने की उम्मीद थी क्योंकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में रनों का पहाड़ खड़ा करने के बाद राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई। भारत पांच मैचों की सीरीज में 1-2 से पीछे है और अगला मैच अभी एक हफ्ते दूर हे, ऐसे में प्रबंधन को फैसला लेना होगा कि नायर के साथ बने रहें या फिर युवा साई सुदर्शन को मौका दिया जाए। जिन्हें अपने पहले मैच के बाद अंतिम एकादश से बाहर कर दिया गया था। बाहर किए गए बाएं हाथ के इस बेहतरीन बल्लेबाज कोई बड़ी गलती नहीं की और ऐसा आठवें नंबर पर एक अतिरिक्त बल्लेबाजी विकल्प को शामिल करने के लिए किया गया। दासगुप्ता ने पीटीआई से कहा कि, आप अब भी सीरीज में बने हुए हैं क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट मैच भी बेहद करीबी था।

दिल्ली में घर का सपना होगा पूरा, डीडीए लाएगा प्रीमियम आवास योजना

(एजेन्सी)।

दिल्ली में फ्लैट खरीदने या अपना घर बनाने का सपना लाखों लोगों का होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही इस सपने को हकीकत में बदल पाते हैं। इसकी मुख्य वजह दिल्ली में प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतें हैं। हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी में रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) एक और प्रीमियम हाउसिंग स्कीम शुरू कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण अगस्त की शुरूआत में प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 लॉन्च करने वाला है। यदि आप इस प्रीमियम आवास योजना में फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको नीलामी में भाग लेना होगा। ई-नीलामी प्रारूप में होने वाली यह नीलामी अगले महीने की शुरूआत में आयोजित की जाएगी। इसके बाद, सफल बोलीदाता का चयन रैंडम ड्रॉ या लॉटरी के माध्यम से किया जा सकेगा। इस प्रीमियम आवास योजना में वसंत कुंज, जसोला (पॉकेट 9बी) और द्वारका (सेक्टर 19बी) में 39 उच्च-आय वर्ग (एचआईजी) फ्लैट, जहाँगीरपुरी, नंद नगरी, द्वारका और पीतमपुरा में 48 मध्यम-आय वर्ग (एमआईजी) फ्लैट और रोहिणी में 22 निम्न-आय वर्ग (एलआईजी) फ्लैट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने बताया कि पॉकेट 9, नसीरपुर, द्वारका में 66 उच्च-आय वर्ग (ईएचएस) फ्लैट और सेक्टर 18, रोहिणी और शालीमार बाग में दो उच्च-आय वर्ग (एसएफएस) श्रेणी-क्क्र फ्लैट भी उपलब्ध कराए जाएँगे।

बेटी के बर्थडे पर भावुक हो गए मोहम्मद शमी

(एजेन्सी)। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने बेटी आयरा के जन्मदिन पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। शमी ने बेटी के 10वें जन्मदिन पर अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए एक संदेश भी लिखा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज शमी ने 17 जुलाई को एक भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से अपनी बेटी आयरा के 10वें जन्मदिन पर उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया। शमी के ये पोस्ट उस समय आई है जब वह पत्नी हसीन जहां से अलग होने के बाद कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही में कोर्ट ने शमी को हसीन जहां और बेटी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। शमी ने पोस्ट में लिखा कि, प्यारी बेटी मुझे आज भी वो सारी रातें याद हैं जब हम जागते रहे। बातें करते रहे, हंसते रहे और खासकर तुम्हारा डांस। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी बड़ी हो रही हो, मैं चाहता हूं कि जिंदगी में तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छी चीजें हों। भगवान तुम्हें आज और हमेशा प्यार, शांति, खुशी और अच्छी सेहत दे। जन्मदिन मुबारक हो। बता दें कि, साल 2018 में हसीन जहां से शमी अलग हो गए थे। तब से वह अपनी बेटी से भी दूर हो गए। आयरा फिलहाल कोलकाता में अपनी मां के साथ रहती है। हसीन जहां ने शमी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। दोनों की शादी तीन साल तक चली थी।

ककराला में मेगा बिजली बिल समाधान शिविर का आयोजन

उपभोक्ताओं ने उठाई बिजली समस्याओं की आवाज

एसबी ब्यूरो प्रमुख/इंतजार हुसैन

बदायूँ। बदायूँ के कस्बा ककराला नगर पालिका परिषद में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा मेगा बिजली बिल समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं को सामने रखा, जिनमें मीटर के अनुसार बिल न आना, मीटर खराब होना, नए मीटर की आवश्यकता, मीटर रीडर का समय पर न आना, मीटर की डिस्प्ले खराब होना और नगर में बिजली की खराब व्यवस्था शामिल थी। शिविर के दौरान उपभोक्ताओं ने नगर में बिजली की अघोषित कटौती, लो वोल्टेज, जर्जर तारों और अन्य समस्याओं को लेकर गहरी नाराजगी जताई। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार हामिद अली खान राजपूत और सभासद असलम खान ने इन समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन अधिशासी अभियंता, विद्युत खंड द्वितीय के नाम उपखंड अधिकारी अमर सिंह व अभियंता राकेश कुमार को सौंपा। ज्ञापन में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने और उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की गई। कार्यक्रम में नगर चेयरमैन इंतखाब मुमताज सकलैनी, अधीक्षण अभियंता अखिलेश कुमार, अभियंता राकेश कुमार, केशव कुमार, कृष्ण कुमार, अभिषेक बाबू, गौरव बाबू, मीटर रीडर और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। शिविर में उपभोक्ताओं की शिकायतों का पंजीकरण किया गया और संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए गए।

यह शिविर बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ, जिसमें उनकी समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का प्रयास किया इस कार्यकर में ककराला बिजली व्यवस्था ग्रुप का भी अहम सहयोग रहा।

राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत ऐसे प्रकरण जिनमें सुलह समझौता के आधार पर समाधान की संभावना अधिक हो, को कराए निस्तारण

संजना भारती संवाददाता
मनोज कुमार बिन्द

प्रयागराज। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरण जिसमें सुलह समझौता के आधार पर समाधान की संभावना अधिक हो तो ऐसे प्रकरणों को उक्त अभियान के अंतर्गत मध्यस्थता के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाना है जिससे वादकारियों को त्वरित न्याय मिल सकेगा व उनके धन व समय की भी बचत होगी।

श्री दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज द्वारा बताया गया कि यह अभियान 30 सितंबर 2025 तक चलाया जाएगा एवं इस अभियान के अंतर्गत न्यायालय में लंबित वैवाहिक विवाद मामले, मोटर दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, लघु आपराधिक मामले, उपभोक्ता विभाग के मामले, ऋण वसूली

के प्रकरण, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले वह अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरणों को शामिल किया गया है। मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना है, बिना अदालत जाये।

मध्यस्थता का प्राथमिक लक्ष्य विवादो को आपसी सहमति से हल करना, दोनो पक्षों को एक-दूसरे की बात सुनने और समझने में मदद करना होता है। मध्यस्थता, पक्षो के बीच संबंधों की बनाए रखने में मदद करती है एवं पक्षों को अपने विवादों को स्वयं हल करने का अधिकार देती है। मध्यस्थता की प्रक्रिया आमतौर पर गोपनीय होती है, जिसका मतलब है कि जो बातें मध्यस्थता में कही जाती है, वे सार्वजनिक नहीं होती है। मध्यस्थता अदालत की कार्यवाही की तुलना में कम खर्चीली होती है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन से एवं विधि व्यवसायियों से अपील है कि वे अपने-अपने प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में माह जुलाई 2025 के अंदर जमा करा कर इस अभियान का लाभ उठाकर एवं अपने मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के आधार पर करा सकते हैं। यह जानकारी श्री दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रयागराज द्वारा प्रदान की गई।

विधिक साक्षरता शिविर में दी गई अधिकारों की जानकारियां

एसबी ब्यूरो प्रमुख इंतजार हुसैन

बदायूं। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निदेशांनुक्रम एवं मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा मध्स्थता के लाभ/पीसीटीएनडीटी अधिनियम के तहत लिंग चयन और बाल लिंग अनुपात में गिरावट एवं पॉश एक्ट के विषय पर गुरुवार को विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन विकास खण्ड-कादरचौक, जनपद बदायूं में आयोजित किया गया।

शिविर का शुभारम्भ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं शिव कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में जिला मिशन कोर्डिनेटर, छवि वैश्य, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी आम जनमानस को केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। असिस्टेन्ट, एलएडीसी कशिश सक्सेना द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी आम जनमानस के विधिक अधिकारों से सम्बन्धित एवं 3 नये कानूनों के बारे में एवं भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद-14, अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद-18, अनुच्छेद-21 व 21ए, एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न टोल फ्री नम्बर 112, 1090, 1076, 15100 इत्यादि के बारे में एवं पोक्सो एक्ट व नये तीन कानून के बारे में बताया एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2013 अधिनियम के अन्तर्गत एवं मारपीट करना ही घरेलू हिंसा नहीं होती है आर्थिक तरीके से भी प्रताड़ित करना भी घरेलू हिंसा होती है के बारे में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया।

शिविर के अन्त में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी जन सामान्य को नालसा, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निदेशांनुपालन में नालसा 2025 के अन्तर्गत जमीनी स्तर पर सूचना और पारदर्शिता के लिए न्याय जागरूकता पहल के लिए जागृति ईकाई, नालसा (डाउन) 2025 के अन्तर्गत न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने, कानूनी जागरूकता फैलाने और नशीली दवाओं के दुरूपयोग के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए डाउन ईकाई 2025 के अन्तर्गत आदिवासी समुदाय के हितों के लिए संवाद इकाई का गठन किया गया है जोकि इन इकाईयों के द्वारा समय-समय पर विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर आम जनमानस को जागरूक करने हेतु प्रेरित करेगीं।

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा स्त्री-पुरुष सामानता सम्बन्धित प्रावधानों एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धित विधिक प्रावधानों को विस्तृत रूप में बताया गया। इसी कम में जनपद न्यायालय परिसर, बदायू में स्थित ए०डी०आर० भवन संचालित न्यायालय स्थायी लोक अदालत की प्रकिया एवं कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी गयी।

इसी क्रम में 13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुपालन में 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्स्थता अभियान चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिक से अधिक निस्तारण किया जा सके।

रोजगार सृजन कार्यक्रम का विधानसभा क्षेत्र में हो रही पुरजोर चर्चा

एसबी ब्यूरो

तेघड़ा/बेगूसराय। 143 विधानसभा क्षेत्र से समाजसेवी सह एयरफोर्स से अवकाश प्राप्त पदाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह उर्फ आनंद जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनके द्वारा रोजगार सृजन कार्यक्रम का अभियान तेज कर दिया गया है। अभी कुल 26 जगहों पर सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण शिविर सुचारू रूप से चल रही है। महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। चंद्रप्रकाश सिंह की लोकप्रियता की चहुंओर प्रसंशा हो रही है।

श्री सिंह ने बताया कि हम तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र को अव्वल बनाएंगे। मुझे तमाम मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। चंद्रप्रकाश सिंह लगातार क्षेत्र के लोगों के सुख-दुख में भाग ले रहे हैं। चंद्रप्रकाश सिंह के सिलाई-कढ़ाई अभियान को बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सराहना करते हुए कहा कि यह मुहिम मिल का पत्थर साबित होगा।

चंद्रप्रकाश सिंह के साथ जनसंपर्क अभियान में कैलाश यादव, सुरेन्द्र सिंह, महेंद्र मलाकार, कपिलदेव मिश्रा, मो. जुबैर, मो. बारिक, मोनू पटेल, कौशल किशोर सहित अन्य गणमान्य जनसंपर्क अभियान में डोर-टू-डोर चल रहे हैं।

अमृतसर में सरहद पार से हथियारों की तस्करी नैटवर्क का पर्दाफाश; 10 पिस्तौलों सहित एक काबू

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़/अमृतसर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए शुरू की मुहिम के दौरान, काउन्टर इंटेलिजेंस अमृतसर ने पाकिस्तान से सम्बन्धित सरहद पार से गैर-कानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले माड्यूल के एक संचालक को .30 बोर की 10 आधुनिक पिस्तौलों और मैगजीनों सहित गिरफ़्तार करके इस माड्यूल का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी यहाँ डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ़्तार किये गए व्यक्ति की पहचान हरजिन्दर सिंह निवासी गाँव डल्ल, तरन तारन के तौर पर हुई है। बताने योग्य है कि वह एक बदनाम नशा तस्कर है जिसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित दो मामले दर्ज हैं और हाल ही में वह जेल से जमानत पर रिहा हुआ है। यह सफलता सीआइ अमृतसर द्वारा सरहद पार से नशीले पदार्थों और गैर-कानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले ऐसे माड्यूल के तीन गुर्गों - सरबजीत सिंह और कुलविन्दर सिंह दोनों निवासी फिरोजपुर और अशमनदीप सिंह निवासी तरन तारन को आठ आधुनिक हथियारों, 1 किलो हेरोइन और 2.9 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद सहित गिरफ़्तार करके इस माड्यूल का पर्दाफाश करने से पंद्रह दिनों के बाद हासिल हुई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि मुलजिम पाकिस्तान आधारित तस्कर जो सरहद पार से हथियारों की खेप भेजने के लिए ड्रोन का प्रयोग कर रहा है, के साथ मिलकर काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि गिरफ़्तार मुलजिम राज्य में आपराधिक गतिविधियों को हवा देने के इराद से राज्य भर के अपराधियों और गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई कर रहा था। इस आपरेशन के बारे जानकारी देते हुये डीजीपी ने कहा कि सीआइ अमृतसर की टीमों को तरन तारन के गाँव डल्ल के नजदीक पड़ते भारत-पाकिस्तान सरहदी क्षेत्र से हथियारों की खेप प्राप्त होने के बारे खुफिया जानकारी मिली थी। उन्होंने बताया कि इस जानकारी पर तुरंत कार्यवाही करते हुये पुलिस टीमों ने संदिग्ध हरजिन्दर सिंह को अमृतसर-झबाल सड़क पर बोहड़ू पुल के नजदीक रोका, जब वह किसी पार्टी को खेप डिलीवर करने जा रहा था और उसके कब्जे में से गैर- कानूनी हथियार बरामद किये। उन्होंने बताया कि इस मामले के अगले-पिछले सम्बन्ध स्थापित करने और उस व्यक्ति जिसको यह खेप डिलीवर की जानी थी, की पहचान करने के लिए आगे जांच जारी है।

सोनू नोल्टा हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजेश कुमार

पंचकूला। सोनू नोल्टा मर्डर केस की जांच में पंचकूला पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच सेक्टर-19 की टीम, जिसमें इंस्पेक्टर निर्मल सिंह प्रमुख रूप से शामिल हैं, ने 16 जुलाई को आरोपी जमील पुत्र रमजान, निवासी गांव कुतबेवाला, थाना पिंजौर, जिला पंचकूला को सैक्टर-20 पंचकूला से गिरफ़्तार किया है। आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी जमील ने हत्या की साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार की है। उसने यह भी कबूल किया है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने अपनी गाड़ी मुख्य आरोपी पीयूष पिपलानी को उपलब्ध करवाई थी। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी की निशानदेही पर कई अहम सुराग और सबूत सामने आएंगे।

रिमांड अवधि के दौरान पुलिस टीम विभिन्न ठिकानों पर रेड कर शेष फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने की दिशा में तेजी से काम करेगी। एसीपी क्राइम ने बताया कि अब तक की जांच में पुलिस को कुछ ठोस सबूत मिले हैं, जो इस मामले को निर्णायक मोड़ पर ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि टीम लगातार कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और बहुत जल्द अन्य आरोपियों को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा।

लम्पी त्वचा रोग टिकाकरण कार्यक्रम की शुरूआत

एसबी ब्यूरो

तेघड़ा/बेगूसराय। बिहार सरकार पशुपालन विभाग बिहार पटना अंतर्गत बेगूसराय जिला में तेघड़ा प्रखंड में लम्पी त्वचा रोग एलएसडी टीकाकरण कार्यक्रम माह जुलाई 2025, 17.7.2025 को तेघड़ा गौशाला में माननीय बिहार सरकार खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता के द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा गौमाता को स्नेहपूर्वक रोटी और गुड़ खिलाकर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह पहल हमारे पशुधन की सुरक्षा और किसानों की आजीविका की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

इस टीकाकरण कार्यक्रम में जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. राकेश कुमार कुमुद, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी तेघड़ा, डॉ. चंद्र मौलेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी तेघड़ा तेघ राकेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉ. रविंद्र प्रसाद मोहन, गौशाला सचिव शिव कुमार केजरीवाल, जदयू मीडिया सेल जिला अध्यक्ष मोनू पटेल सहित पशुपालन विभाग तेघड़ा के कर्मी एवं टीका कर्मी भी उपस्थित थे।

बिहार विधानसभा 2025 को लेकर मतदाताओं के पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्र जमा नहीं करने वाले का मतदाता सूची से कटेगा नाम, अन्यथा समय से करें जमा-बीडीओ

बीएलए के साथ बीएलओ ने की बैठक, छूटे हुए गणना प्रपत्र जमा करने का किया आग्रह

संजना भारती संवाददाता
अर्जुन कुमार झा

समस्तीपुर। खानपुर आगामी बिहार विधान सभा चुनाव 2025 के मद्देनजर मतदाताओं के गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत खानपुर प्रखंड क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलए एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ बीएलओ ने बैठक आयोजित किया। इस दौरान बीएलओ ने बताया कि अब तक करीब 80 प्रतिशत मतदाताओं ने अपना अपना गणना प्रपत्र भरकर जमा कर दिए हैं। अब तक जो मतदाता गणना प्रपत्र भरकर नहीं दिए हैं उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। इसीलिए आप लोग अप्राप्त प्रपत्र का अध्ययन कर लें और इस पुनीत कार्य में हमें मदद करें। ताकि कोई योग्य मतदाता छुटे नहीं। बीएलओ ने कहा जो लोग संबंधित आवश्यक कागजात नहीं दिए हैं। उन्हें भी समय रहते उपलब्ध कराना है। इसकी समुचित जानकारी सभी मतदाताओं को दे दी जाय। इस दौरान सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार चंद्रा ने प्रखण्डाधीन मतदान केंद्रों का दौरा किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि जो मतदाता गणना प्रपत्र भरकर जमा नहीं करेंगे उनका नाम मतदाता सूची से हट जाएगा। अतः समय रहते सभी योग्य मतदाताओं का गणना प्रपत्र जमा कर दिया जाय। उन्होंने बीएलए के माध्यम से सभी जानकारी आम आवाम को देने की बात कही।

मौके पर आपूर्ति पदाधिकारी राकेश कुमार, सीडीपीओ वर्षा सिन्हा, पर्यवेक्षक भीम कुमार यादव, श्याम कुमार पांडेय, मिथिलेश कुमार सिंह, बीएलओ मास्टर ट्रेनर लाल बाबू, दिलीप कुमार राम, संजय कुमार, बैद्यनाथ राम, योगेंद्र मांझी, बीएलए विजय कुमार कुशवाहा, बिरजू कुमार सहनी, दिलीप कुमार, सुधीर कुमार आदि उपस्थित रहे।

उपखंड अधिकारी ने किया प्यावड़ी विधालय का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

संजना भारती संवाददाता/एस रहमान

टोंक। पीपलू उपखंड अधिकारी गणराज बडगोती ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्यावड़ी का औचक निरीक्षण किया गया। विद्यालय परिसर मे अध्ययन-अध्यापन सुचारू रूप से पाया गया। विद्यालय परिसर की साफ सफाई संतोषप्रद पाई गई। विद्यालय में शौचालय व पेयजल की सुविधा सुचारू पाई गई। विद्यालय में उपखंड अधिकारी द्वारा कक्षा में छात्रों से सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्नोत्तर भी किए। गत परीक्षा परिणाम का तुलनात्मक अवलोकन करने पर पाया गया की 10वीं व 12वीं कक्षा का गुणात्मक परिणाम विषयों में अत्यंत

अंतर पाया गया विशेषकर दसवीं कक्षा में विज्ञान व सामाजिक विज्ञान में अन्य विषयों की तुलना में प्रथम श्रेणी में न्यून छात्र ही उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार कक्षा 12 में इतिहास विषय में अन्य विषयों की तुलना में कम छात्र प्रथम श्रेणी में आए। गुणात्मक परिणाम में विद्यालय का सही नहीं आया, जिसमें से भी उक्त विषयों का परिणाम अपेक्षाकृत अत्यंत न्यू रहा है। पीपलू आशान्वित ब्लॉक होने तथा गुणात्मक विषयों का इंडिकेटर होने के कारण शिक्षा विभाग का प्रदर्शन भी कम रहा है अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्यावड़ी को उक्त कार्मिकों सामाजिक विज्ञान, विज्ञान व इतिहास के अध्यापकों को स्पष्टीकरण व अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ज्ञात रहे कि उपखंड अधिकारी गणराज बड़गोती पीपलू उपखंड क्षेत्र के विधालयो का औचक निरीक्षण कर रहे हैं।

लाल चंद कटारूचक्क ने 5 जिलों में हाईवे पर फूलों वाले पौधे लगाने सम्बन्धी पायलट प्रोजैक्ट का किया ऐलान

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। वातावरण को साफ-सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए कई अहम पहलकदमियों का ऐलान करते हुए वन और वन्य जीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज हाईवे के दोनों तरफ फूलों वाले पौधे लगाने वाले एक पायलट प्रोजैक्ट का ऐलान किया। एक राज्य स्तरीय विशेष कमेटी इस प्रोजैक्ट की निगरानी करेगी और समय-समय इसकी समीक्षा भी करेगी। शुरूआती दौर में, यह प्रोजैक्ट 5 जिलोंः रोपड़ (विशेष तौर पर श्री आनन्दपुर साहिब), शहीद भगत सिंह नगर (शहीद भगत सिंह के पैतृक गाँव खटकड़ कलां के आसपास के क्षेत्र में), संगरूर, पठानकोट और अमृतसर में लागू किया जायेगा। प्रोजैक्ट के अंतर्गत इन जिलों में हाईवे के दाएं-बाएं दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी पर 5, 6 और 7 फुट तक की ऊँचाई वाले पौधे लगाए जाएंगे।

मंत्री ने पंजाब भवन में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये कहा कि पौधों के बढ़ने-फुलने और देखभाल को यकीनी बनाने के लिए उचित निगरानी की जायेगी। इसके इलावा, बाड़ लगाने का काम भी किया जायेगा जिससे पौधों को आवारा जानवरों से बचाया जा सके। इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुये कटारूचक्क ने बताया कि यह प्रोजैक्ट आसपास को बहुत साफ-सुथरा और हरा-भरा बनाने की तरफ एक सहृदय प्रयास है। मंत्री ने कहा कि यह प्रोजैक्ट मनरेगा के अधीन काम करते लोगों के लिए रोजगार के नये मौके भी यकीनी बनाऐगा। दूसरी अहम पेशकदमी का उद्घाटन करते हुये मंत्री ने बताया कि आज की पीढ़ी को वृक्षों और वातावरण के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए इस विषय पर आधारित भाषण और कविता मुकाबले 23 जुलाई से बटाला में प्रसिद्ध कवि शिव कुमार बटालवी के जन्म दिवस वाले दिन से शुरू करवाए जाएंगे। यह मुकाबले एक महीने तक चलेंगे और चार श्रेणियोंः प्राइमरी (पहली से पाँचवी कक्षा), सेकंडरी (छटी से दसवीं कक्षा), सीनियर सेकंडरी (ग्यारहवी और बारहवीं) और कालेज स्तर पर करवाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री सैनी ने परियोजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा कर सभी परियोजनाओं को तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को जल्द से जल्द इन परियोजनाओं को समर्पित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव कार्यालय, गृह विभाग, श्रम विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य, मत्स्य और आयुष विभागों सहित अन्य विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकसित भारत के चार स्तंभ युवा, महिला, किसान और गरीब के कल्याणार्थ नीति निर्माण करने और नियमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीतियां बनाते समय इन वर्गों की वास्तविक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए तथा योजनाओं में समावेशिता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने यमुनानगर के प्लाईवुड उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिए ताकि इस क्षेत्र के बरसों पुराने प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, जगाधरी के धातु उद्योग को भी पुनर्जीवित करने के लिए मास्टर-प्लान बनाने के भी निर्देश दिए।

नायब सिंह सैनी ने निर्देश देते हुए कहा कि वॉक-टू-वर्क नीति के तहत सरकार की कार्यस्थलों के नजदीक के शहरों में श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इसके लिए सीएसआर के तहत कॉरपोरेट संस्थानों को जोड़ने की संभावनाएं तलाशी जाएं। इसके क्रियान्वयन से श्रमिकों को सस्ती दरों पर आवास सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि इन आवासीय क्षेत्रों में कैंटीन की सुविधा भी विकसित करने की कार्य-योजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र के अनुसार उत्पादित होने वाली फसलों के अनुरूप वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की कार्य-योजना बनाई जाए, ताकि किसान भी परंपरागत फसलों के अलावा मार्केट के अनुसार फसलों की खेती कर सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि छोटे-छोटे क्लस्टर चिह्नित करके फसलों के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एक मजबूत सड़क सुरक्षा नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख मार्गों पर कहीं भी गड्ढे न हों, साथ ही, जिन स्थानों पर बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें "ब्लैक स्पॉट्स" के रूप में चिन्हित कर वहां त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी सर्दियों के मौसम, धुंध व कोहरे को देखते हुए दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़कों पर उपयुक्त साइनेज लगाए जाएं।

बैठक में जानकारी दी गई कि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा स्टार्टअप नीति का विस्तार करने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व 45 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है और इसे 60 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके लिए नीति आयोग के सहयोग से पंचकूला में एक केंद्र स्थापित करने की योजना है और इस केंद्र में वित्तीय प्रोत्साहनों के अलावा महिलाओं को स्टार्टअप से संबंधित ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बैठक में बताया गया कि प्रदेशभर में हर योगशाला के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, मत्स्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ राजा शेखर वुंडरू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

आवश्यक सूचना

तेजी से बढते राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र, '**संजना भारती**' को चंडीगढ़, पंचकुला सहित पूरा हरियाणा, पंजाब में जिला स्तर, तहसील स्तर, खंड स्तर पर पत्रकार/कोर्सपोंडेट/ प्रतिनिधि, जिला प्रभारी की जरूरत है।
संपर्क करें: 9871221635

समाधान शिविर के माध्यम से आमजन को मिल रही समस्याओं से राहत: सीटीएम

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। सीटीएम गुरविंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के निदेर्शानुसार एवं डीसी प्रीति के मार्गदर्शन में नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के उद्देश्य से लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों का सुना गया और उनका समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि समाधान शिविरों के माध्यम से आमजन की शिकायतों का निवारण करके बड़ी राहत देने का काम किया जा रहा है। छोटी-छोटी त्रुटियों की वजह से जिन लोगों के काम रुके हुए थे, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों को समयबद्ध और प्रभावी समाधान प्रदान करना है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी समाधान शिविर में आने वाले शिकायतों को गंभीरता के साथ सुने और उनका प्राथमिकता के साथ समाधान करें, ताकि उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। हर रोज अपना पोर्टल जरूर चेक करें और निर्धारित समय पर एक्शन टेकन रिपोर्ट अपलोड करें। उन्होंने आमजन से भी आह्वान किया कि वे किसी भी समस्या के समाधान के लिए उससे संबंधित आवश्यक दस्तावेजों जरूर लेकर आएं, ताकि समस्या का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

कल्पना को छूने दो आसमान नामक चित्रकला प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग लें विद्यार्थी: नसीब सैनी

आठ अगस्त को पंचकूला में करवाई जा रही है चित्रकला प्रतियोगिता

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी नसीब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा कल्पना को छूने दो आसमान नामक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 12 अगस्त को 2025 को पंचकूला के यवनिका गार्डन, सेक्टर-5 में आयोजित की जाएगी। विद्यार्थी इसमें बढ़चढ़ कर भाग लें और 21 जुलाई तक artandculturalafairshry@gmail.com पर ईमेल भेज कर आवेदन करें।

उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता को दो आयु वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी में 6 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्टोरी टेलिंग विषय पर पेंटिंग बनानी होगी, जबकि द्वितीय श्रेणी में 11 से 16 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागी माई विजन विषय पर अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूली बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करने एवं उन्हें प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

डीआईपीआरओ नसीब सैनी ने बताया कि प्रत्येक श्रेणी में आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। दोनों श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार के रूप में 7100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 2100 रुपये नकद दिए जाएंगे। इसके अलावा पांच सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। साथ ही, प्रतियोगिता में सर्वाधिक भागीदारी वाले विद्यालय को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रतिभागियों को ड्रॉइंग शीट, रंग तथा अन्य आवश्यक सामग्री स्वयं लेकर आनी होगी। वे ऑयल पेंट, एक्रेलिक कलर, पेंसिल कलर, पोस्टर कलर या किसी भी माध्यम से अपनी पेंटिंग बना सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक विद्यार्थी 21 जुलाई, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए प्रतिभागी artandculturalafairshry@gmail.com पर ईमेल भेजें। अधिक जानकारी के लिए 0172-2793971 या 0172-2793987 (प्रातः: 9 बजे से सायं 5 बजे तक) पर संपर्क किया जा सकता है।

सभी इंजीनियरिंग कार्य केवल एचईडब्ल्यूपी के माध्यम से आवंटित किए जाए-मुख्यमंत्री

विभाग ठेकेदारों को समय पर ऑनलाइन भुगतान करे सुनिश्चित

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री धारक बेरोजगार शिक्षित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु एक नई योजना हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना शुरू की है। निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, इन युवाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी यहां हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना इंजीनियरिंग योग्यता प्राप्त युवाओं को अपने क्षेत्र में करियर के नए अवसर प्रदान करेगी, जिससे उनके पेशेवर विकास को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमशीलता के बेहतर रास्ते खुलेंगे। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय ने योजना के तहत पात्र एवं इच्छुक इंजीनियरिंग युवाओं के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल https://stt.iti-haryana.gov.in लॉन्च किया है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, पलवल में निर्धारित 90-दिवसीय प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, युवा एचईडब्ल्यू पोर्टल पर सूचीबद्ध होने के लिए पात्र होंगे। ठेकेदारों की पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए, श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि बाधा मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर ठेकेदार पंजीकरण के लिए एक स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) परिभाषित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एक बार अपेक्षित दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर दिए जाने के बाद, ठेकेदारों को आगे की प्रक्रिया के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता न हो। उन्होंने सम्बंधित सभी विभागों को ऑनलाइन माध्यम से ठेकेदारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्हें बताया गया कि वर्तमान में 20,709 ठेकेदार जुड़े हुए हैं, जिनमें से 6,476 पंजीकृत हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए एचईडब्ल्यूपी पोर्टल पर एक प्रावधान जोड़ा जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो। विभिन्न विकास परियोजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग किसी भी विकास कार्य या परियोजना के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय पर्याप्त बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। समय पर कार्य पूरा करने तथा देरी को रोकने के लिए यह आवश्यक है। ऐसे मामलों में जहां विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जानी है, विभाग को संबंधित मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि धनराशि शीघ्र जारी की जा सके।

हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) के माध्यम से निविदा आवंटन की प्रगति की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि निविदाएँ जारी होने के तुरंत बाद आवंटित की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि विभागों के सभी इंजीनियरिंग कार्य केवल एचईडब्ल्यूपी के माध्यम से आवंटित किए जाएँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विभाग को ऑफलाइन निविदाएँ जारी करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागीय भुगतान एचईडब्ल्यूपी प्रणाली में पूरी तरह से एकीकृत किए जाएँ।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि 1 अप्रैल, 2025 से एचईडब्ल्यूपी पर किसी भी ऑफलाइन आवंटन की अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें यह भी बताया गया कि निविदाओं के आवंटन में देरी को रोकने और समय पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक सोमवार को ऑनबोर्ड विभागों के ईआईसी को एसएमएस भेजने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, वित्त विभाग ने ठेकेदारों के बिलों के भुगतान की सुविधा के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के साथ एकीकरण के लिए चार बैंकों को अधिकृत किया है।

बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, लोक निर्माण (भवन एवं सडकें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाइन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

नीलोखेड़ी में मनरेगा अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

सरकार की योजनाओं का असर अधिकारियों की समर्पित कार्यशैली से ही संभव: डॉ. वीरेन्द्र सिंह चौहान

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी में देशभर से आए मनरेगा अधिकारियों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम का समापन समारोह बुधवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आंध्र प्रदेश सरकार में मनरेगा निदेशक तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारी वाई.वी. षण्मुख कुमार ने की।

इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. वीरेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि जब अधिकारी खुले मन से और समर्पित होकर कार्य करते हैं, तभी योजनाएं जमीनी स्तर पर चमत्कारिक परिणाम देती हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों के जिन ग्राम पंचायतों में हुए बेहतरीन कार्यों से रूबरू कराया गया, उनके प्रेरणादायक उदाहरणों को अधिकारी अपने-अपने राज्यों में लागू करने का प्रयास करें।

आंध्र प्रदेश के मनरेगा निदेशक वाई.वी. षण्मुख ने हरियाणा में गंदे पानी के प्रबंधन और ग्राम स्तर पर नर्सरी विकसित करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य राज्य भी हरियाणा के अनुभवों से सीख लेकर इन्हें अपनाएं।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के फैकल्टी डॉ. राजेश्वर ने आयोजकों को सफल कार्यक्रम के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देशभर से मनरेगा योजना में कार्यरत कुल 27 अधिकारियों ने भाग लिया।

भ्रमण के दौरान अधिकारियों को करनाल के सुलतानपुर, बूटेड़ी और कुरुक्षेत्र जिले के कोल्हापुर व ईशरगढ़ गांवों में मनरेगा के अंतर्गत किए गए उत्कृष्ट कार्यों का अवलोकन कराया गया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम से जुड़े अनुभव साझा करते हुए इसे बेहद उपयोगी बताया।

समापन समारोह में ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा के सिस्टम एनालिस्ट संदीप वाही, सहायक प्रोफेसर संदीप भगद्वाज, सुशील मेहता और कमलदीप सांगवान सहित संस्थान के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

प्रीमियम की अंतिम तारीख 31 जुलाई, किसान जल्द कराएं फसल बीमा: डीसी उत्तम सिंह

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा खरीफ-2025 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को 31 जुलाई, 2025 तक आवेदन करने का मौका दिया गया है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे भारी बारिश, सूखा, कीट प्रकोप, ओलावृष्टि आदि से फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि जो किसान धान, बाजरा, मक्का व कपास जैसी फसलें बो रहे हैं, वे इस योजना के तहत बीमा करवाकर आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को प्रीमियम राशि धान के लिएः रु2124.98 प्रति हेक्टेयर बाजरा के लिएः रु1024.36 प्रति हेक्टेयर मक्का के लिए रु1089.74 प्रति हेक्टेयर व कपास के लिए रु5435.05 प्रति हेक्टेयर दरों से देनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना ऋणी व गैर ऋणी दोनों प्रकार के किसानों के लिए उपलब्ध है। यदि कोई ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहता है, तो उसे अंतिम तिथि से कम से कम सात दिन पहले यानी 24 जुलाई, 2025 तक संबंधित बैंक को लिखित रूप में सूचित करना होगा।

इसके अलावा, बीमा न करवाने के लिए पोर्टल के माध्यम से ओटीपी आधारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें किसान के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे बैंक को प्रस्तुत करने के बाद ही ओटीपी-आउट फॉर्म स्वीकार किया जाएगा।

गैर ऋणी किसान, जो बीमा करवाना चाहते हैं, उन्हें जमीन की फर्द, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, फसल गांव विवरण व फसल बिजाई प्रमाण पत्र दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) से संपर्क करना होगा। डीसी ने सभी किसानों से अपील की कि वे इस योजना का समय रहते लाभ लें ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने किया महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण

कोरियावास में इसी वर्ष से एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू करने के प्रयास में सरकार

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रही है। महेंद्रगढ़ जिला के कोरियावास में अरावली की वादियों के बीच बना महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान है। कनेक्टिविटी, लोकेशन तथा वातावरण के हिसाब से यह हरियाणा का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है। सरकार का प्रयास है कि इसी वर्ष से एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू की जाएं। यहां छात्रावास, अस्पताल विंग तथा शैक्षणिक ब्लॉक पूरी तरह से तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्री महेंद्रगढ़ जिला के कोरियावास में स्थित मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमबीबीएस सीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। वर्ष 2014 में जहां 700 सीटें थीं, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 2185 हो गई है और भविष्य में इसमें और भी वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य बजट में लगातार वृद्धि कर रही है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 'उज्जवल दृष्टि योजना' के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह योजना हरियाणा में पहली बार लागू की गई है। इसमें पूरे राज्य में मुफ्त चश्मे वितरित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इससे पहले मेडिकल कॉलेज भवन के शैक्षणिक ब्लॉक में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने चिकित्सा विंग तथा छात्रावास का भी निरीक्षण किया।

एसपी आस्था मोदी के कुशल नेतृत्व में जिला पुलिस के बेहतर प्रयासों से अपराध के आंकड़ों में आई भारी कमी

कैथल पुलिस आमजन की सुरक्षा और सेवा के लिए हमेशा तत्पर: एसपी

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। एसपी आस्था मोदी के कुशल नेतृत्व और दिशा-निदेर्शों के तहत कैथल पुलिस ने वर्ष 2025 में अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। जिले में अपराध के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जो आमजन के सहयोग और पुलिस की मुस्तैदी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 के पहले छह माह में लूट, छीना झपटी, गृह भेदन, चोरी, बलात्कार तथा छेड़छाड़ जैसे संगीन अपराधों के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2024 के प्रथम 6 माह में डकैती के 2 मामले सामने आए थे, जबकि वर्ष 2025 में अब तक डकैती का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

एसपी आस्था मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अपराधियों को शीघ्र अति शीघ्र गिरफ्तार किया जा सके और आमजन में सुरक्षा की भावना बनी रहे। जिले में नशा तस्करी और संगठित चोरी के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियानों के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2025 के दौरान अब तक 59 मामलों में 92 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चोरी करने वाले 12 गैंगों के कुल 41 सदस्यों को भी पकड़कर 127 केसो को सुलझाने में सफलता हासिल की गई, जिससे क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगा है। इस वर्ष मर्डर के 19 मामले दर्ज हुए जो पुलिस द्वार त्वरित कार्रवाई दौरान सभी मामलों को सुलझाकर अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। इसके अलावा वर्ष 2025 दौरान अवैध असला अमुनेशन रखने के 23 मामलों में 34 आरोपियों को काबू करके 23 अवैध पिस्तौल व 15 कारतूस बरामद किए गए है। एसपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के निर्देशानुसार समस्त हरियाणा में पुलिस द्वारा प्रभावशाली ढंग से अपराध पर अंकुश व अपराधियों पर नकेल कसी गई है। जो पूरे हरियाणा में मर्डर, लुट, डकैती, छीना झपटी, गृह भेदन, चोरी, बलात्कार, अपहरण तथा छेड़छाड़ जैसे संगीन अपराधो में 16 प्रतिशत कम मामले हुए है। पुरी हरियाणा पुलिस लोगो की सुरक्षा व सेवा के लिए तत्पर है।

एसपी कैथल आस्था मोदी।

एसपी ने बताया कि पुलिस टीमों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर, निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। सीसीटीवी नेटवर्क, गश्त गाड़ियां, और सूचना तंत्र के माध्यम से अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही पुलिस आमजन से भी अपील करती है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी थाने को दें।

कैथल पुलिस आमजन की सुरक्षा और सेवा के लिए हमेशा तत्पर है और एसपी आस्था मोदी ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाया जाए।

आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की जाती है कि वे पुलिस के साथ मिलकर अपराध मुक्त समाज के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें। आपसी विश्वास और सामूहिक प्रयास से ही सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण की स्थापना संभव है।

सभी बीपीएल/एएवाई कार्ड धारकों करें अपना ई-केवाईसी: निशांत राठी

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक निशांत राठी ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार सभी बीपीएल/एएवाई कार्ड धारकों की ई-केवाईसी की जानी है, ताकि भविष्य में सरकार की योजनाओं का लाभ लिया जा सकें। इसके लिए सरकार द्वारा सभी बीपीएल/एएवाई लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के लिए मेरा ई-केवाईसी नाम से मोबाइल एप लांच की गई है। सभी बीपीएल/एएवाइ कार्ड धारकों से अपील है कि वे जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में किसी भी लाभार्थी को राशन लेने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा सभी कार्ड धारक अपने नजदीकी डिपो धारक के पास जाकर भी अपनीच ई-केवाईसी करवा सकते है। इसके अलावा ग्राम पंचायत सरपंच/पंचायत पंच व शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षदों से भी अनुरोध है कि वे अपने-2 गांव/वार्ड में बीपीएल/एएवाई कार्ड धारकों को जागरूक करें कि मोबाइल एप के माध्यम से या नजदीकी डिपो धारक के पास जाकर पीओएस मशीन के माध्यम से अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करा सकते है।